भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 10

उत्तर देने की तारीख 25 नवंबर, 2024

सोमवार, 4 अग्रहायण 1946 (शक)

कौशल अंतर को कम करने के लिए कार्यबल

10. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2018 में कौशल अंतर को कम करने के लिए कार्यबल का गठन करने हेतु वर्ल्ड इकनोमिक फोरम और इन्फोसिस के साथ भागीदारी की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त कार्यबल द्वारा कितने लक्ष्य हासिल किए गए हैं;

(ग) क्या कौशल विकास और उद्यमिता संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2015 में यह घोषणा की गई थी कि वर्ष 2020 तक देश के 25 प्रतिशत विद्यालय कौशल को औपचारिक शिक्षा के साथ एकीकृत करने का उद्देश्य रखेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और देश में कितने विद्यालयों ने कौशल को औपचारिक शिक्षा के साथ एकीकृत किया है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) जी हां, भारत में कौशल अंतराल को कम करने के लिए इन्फोसिस और विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। टास्क फोर्स का लक्ष्य भारत में कौशल अंतराल को कम करने और भारतीय कार्यबल को भावी रोजगार हेतु तैयार करने के लिए एक कार्य योजना विकसित करना था।

इसके प्रारम्भ होने के बाद, क्लोजिंग द स्किल्स गैप एक्सेलेरेटर इंडिया ने राष्ट्रीय कार्य योजना को अंतिम रूप देने और 4 कार्य समूहों को आरंभ करने के लिए इंडिया इकोनॉमिक समिट 2019 सहित कई भौतिक बैठकों के लिए नेतृत्व समूह को बुलाया। एक्सेलेरेटर के सदस्यों को अभिनव सहयोगी परियोजनाओं के माध्यम से 4 कार्य समूहों में से एक या अधिक को चुनने और योगदान करने का अवसर मिला। एक्सेलेरेटर ने राष्ट्रीय कार्य योजना की पुष्टि की; हालाँकि, कोविड-19 महामारी के कारण काम और भी रुक गया। महामारी के बाद, चर्चाओं ने ऐसे आदर्श और पहलों की आवश्यकता को मजबूत किया जो गतिशील रोजगार परिवर्तन, रोजगार सृजन और रोजगार की गुणवत्ता में सुधार को गति दे सकते हैं।

(ग) जी हाँ। राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता नीति 2015 के नीतिगत ढांचे के अनुसार, कौशल विकास को आकांक्षापूर्ण बनाने के लिए अगले 5 वर्षों में 25 प्रतिशत स्कूल कक्षा 9 से औपचारिक शिक्षा के साथ कौशल विकास को एकीकृत करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में सभी शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने की सिफारिश की है।

(घ) देश में औपचारिक शिक्षा के साथ कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए कुल 29,342 स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 18,003 स्कूलों में इसे लागू किया गया है, जिनमें 24,55,215 छात्रों का नामांकन हुआ है।

*****